भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की प्रवृत्तियां

राजकिशोर धामाणी

सह अचार्य अर्थशास्त्र

बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर (राज.)

शोध सारांश - भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का दायरा निरन्तर बढ़ता जा रहा है, साथ ही इसके मानकों में भी उदार प्रवृत्ति को अपनाया जा रहा है क्योंकि देश के तीव्रतम आर्थिक विकास के लिए निवेश व तकनीकी की अत्यन्त आवश्यकता है, जो हमें विदेशों से प्राप्त हो सकती है, इसीलिए वर्तमान में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश पर अधिकाधिक ध्यान केन्द्रित कर विदेशी नीतियों में परिवर्तन किया जा रहा है, परन्तु इसके साथ ही साथ यह भी ध्यान रखना आवश्यक होगा कि इसके सामने कहीं हमारा घरेलू उद्योग व्यापार बौना न रह जाए। युवाओं के रोजगार, उत्पादन, जनता की क्रयशक्ति पर सकारात्मक प्रभाव ही भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाकर विकसित देश की श्रेणी में खड़ा कर सकता है जबकि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की नीतियों को देशहित में क्रियान्वित किया जाए व इसके सभी पहलूओं पर गहराई से विचार करते हुए उचित मॉडल अपनाया जाए। भारत की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, भौगोलिक तथा पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुसार ही विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि आर्थिक विकास के साथ-साथ सभ्यता, संस्कृति, पर्यावरणीय तथा मानवीय मूल्यों एवं हितों का संरक्षण भी अत्यन्त आवश्यक है।

प्रस्तावना - विश्व में आर्थिक विकास को गति देने के लिए विकासशील देशों को किसी न किसी सीमा तक विदेशी सहायता पर निर्भर रहना पड़ता है। वर्तमान में एशिया के अन्य विकसित राष्ट्र अपने यहां विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को आकर्षित कर उत्तरोतर विकास के पथ पर अग्रसर हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में भी स्वतंत्रता के पश्चात किसी **न** किसी रूप में विदेशी सहायता ली जाती रही है।

विदेशी पूंजी एक व्यापक शब्द है, जिसके अन्तर्गत-

(1) विदेशी सहायता, जिसमें विकसित देशों की सरकारों और अन्तर्राष्ट्रीय वित्त संस्थाओं द्वारा देश के आर्थिक विकास की **दर** को तेज करने के लिए - (i) अनुदान (ii) रियायती पर ऋण दिये जाते हैं।

(2) व्यापारिक ऋण, जिसमें विदेशी बैंकों से लिए गए ऋण व अनिवासी भारतीयों की जमा को व्यापारिक ऋणों का हिस्सा मान लिया जाता है। (3) विदेशी निवेश 51% x इक्विटी तक के विदेशी निवेश के लिए स्वतः स्वीकृति के लिए 1991 में नये आर्थिक सुधारों को अपनाने के पश्चात् विदेशी निवेश को और अधिक उदार बनाया गया विदेशी निवेश में **(i)** विदेशी प्रत्यक्ष निवेश **(**Foreign Direct Investment) कोई विदेशी नागरिक अथवा संगठन या कंपनी का दूसरे देश में किया गया निवेश प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) कहलाता है, ऐसे निवेश से निवेशकों को दूसरे देश की उस कंपनी के प्रबन्धन में कुछ हिस्सा हासिल हो जाता है।

भारत में यह निवेश भारतीय रिजर्व बैंक, औद्योगिक सहायता सचिवालय (Secretarial for Industrial Approvals SIA) एवं विदेशी निवेश प्रोत्साहन बोर्ड (Foreign Investment Promotion Board - FIPB) के माध्यम से होता है। इसके अन्य दो रास्ते हैं- अनिवासी भारतीय तथा अनिवासियों द्वारा भारतीय कम्पनियों के शेयरों की खरीद

(ii) पोर्टफोलियो निवेश (Protfolio Investment**) -** इसके अन्तर्गत विदेशी कम्पनियां भारतीय कम्पनियों के ऋण-पत्र (बॉण्ड) या अंश (शेयर) खरीदकर विनियोग करती हैं। इस प्रकार के निवेश में विदेशी कम्पनियों का स्वामित्व, प्रबन्ध व नियन्त्रण न होकर लाभांश व ब्याज प्राप्त करने तक सीमित होता है। यह सब स्वदेशी होता है।

भारत के सन्दर्भ में पोर्टफोलियों निवेश का आशय विदेशियों या विदेशी संस्थागत विनियोग (F.I. I.) या भूमण्डलीय न्यासी रसीद (*Global Depository Receipts*-GDRs) या अमरीकी न्यासी रसीद *(Americal* Depository Receipts-ADRs) या अपटीय फण्ड एवं अन्य (Offshore Fund and Others) द्वारा घरेलू पूंजी बाजार में प्रतिभूयिों में निवेश से है। इस प्रकार प्रत्यक्ष निवेश अपनी कम्पनी के प्रबन्ध व उन्नति में प्रत्यक्ष **रूप से** कार्य करते हैं परन्तु (पोर्टफोलियो) विनियोग **में** कम्पनी के विकास व प्रबन्ध में कोई प्रत्यक्ष योगदान नहीं होता।

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) पोर्टफोलियो निवेश की तुलना में अधिक तरल होते हैं। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) आसानी से तरलता में परिवर्तित नहीं किए जा सकते। इसलिए इनमें निवेश करने से पहले कई तथ्यों, जैसे- राजनीतिक स्थिरता, सरकार की नीतियां, आर्थिक व औद्योगिक विकास के अवसर आदि पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। दूसरी ओर, पोर्टफोलियो निवेश को आसानी से तरलता में परिवर्तित किया जा सकता है। (iii) विदेशी सहयोग (Foreign Collaboration) - इधर कुछ वर्षों में स्वदेशी पूंजी तथा विदेशी पूंजी की संयुक्त भागीदारी को सरकार द्वारा प्रोत्साहित किया जा रहा है। विदेशी पूंजी के साथ विदेशी तकनीक का भी सहयोग प्रायः जुटा रहता है। यह विदेशी सहयोग निजी उद्योगपतियों के बीच, विदेशी पक्ष तथा सरकार एवं दो पक्षों की सरकारों के बीच हो रहा है।

विदेशी सहयोग, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एवं पोर्टफोलियो निवेश के माध्यम से विदेशी पूंजी को आकर्षित किया जा सकता है। भारत जैसे विकासशील देश में जहां पूंजी एवं आधुनिक तकनीकी का अभाव है, विकास की दृष्टि से विदेशी पूंजी का विशिष्ट महत्व है।

प्रस्तुत शोध पत्र में भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की प्रवृत्तियों का अध्ययन कर निष्कर्ष निकाले गए हैं।

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के रूट्स - विदेशी निवेश के निम्नलिखित रूट हैं-

1. **ऑटोमेटिक रूट** - इस योजना के अन्तर्गत भारतीय कम्पनियां 10 करोड़ अमरीकी डॉलर (दक्षेस देशों में 15 करोड़ अमरीकी डॉलर) का निवेश कर सकती हैं। यह शर्त है कि यह निवेश भूसम्पत्ति उन्मुख न हो, इस प्रकार ६ के निवेश का वित्त पोषण भारतीय कम्पनी के मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खाते से किया जा सकता है। इस प्रकार के निवेश की जानकारी बाद में रिजर्व बैंक को दे देनी चाहिए।

2. **विदेशी आर्थिक क्षेत्र इकाइयां** - यह इकाइयां ऑटोमेटिक रूप से 10 करोड़ अमरीकी डॉलर की सीमा के बाहर भी विदेश में कितना भी पूंजी निवेश कर सकती है। इसमें कम्पनी के मुद्रा - अर्जक विदेशी मुद्रा खाते से निवेश किया जा सकता है।

3. **ए. डी. आर. / जी. डी. आर. ऑटोमेटिक शेयर /** अदला-**बदली रूट -** इस तरीके के अन्तर्गत भारतीय कम्पनियां अपने ए. डी. आर. / जी. डी. आर. के नए निर्गम के बदले उतने ही महत्व वाली गतिविधि में 10 करोड़ अमरीकी डॉलर या पिछले साल का निर्यात - कमाई के दस गुने के बराबर की अदला- बदली कर सकती है। शर्त यह है कि बाद में रिजर्व बैंक को इसकी सूचना दे दी जाए।

4. **ए. डी. आर. / जी. डी. आर. ऑटोमेटिक रूट** इस स्कीम के तहत् भारतीय कम्पनियां ए.डी.आर./जी. डी. आर. से मिली राशि का शत-प्रतिशत उपयोग किसी सीमा के बिना ऑटोमेटिक रूप से विदेशी निवेश कर सकती हैं। शर्त यह है कि बाद में इसकी सूचना रिजर्व बैंक को दे दी जाए।

5. **भागीदारी** फर्मों **द्वारा निवेश -** भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के अधीन कोई भागीदारी फर्म भी, जो विनिर्दिष्ट व्यावसायिक सेवा देती हो, बिना रिजर्व बैंक की पूर्वानुमति (बाद में रिपोर्ट दे दे) किसी एक वित्त वर्ष में **वैसी ही** गतिविधि में लगी विदेशी कम्पनी में 10 लाख अमरीकी डॉलर या इसके बराबर राशि लगा सकती है।

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश - सीमाओं व रूट में परिवर्तन

भारत में विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग की प्रवृत्तियां - भारत में 1991 की औद्योगिक **नीति** की घोषणा के पश्चात भारत में प्रत्यक्ष निवेश व पोर्टफोलियो निवेश दोनों के ही अन्तर्प्रवाह में तेजी से वृद्धि हुई।

2015-16 के दौरान कुल एफडीआई अन्तर्प्रवाह (जिसमें साम्यता, अन्तर्प्रवाह, कमाई का पुनर्निवेश तथ अन्य पूंजी सम्मिलित है) 55.457 बिलियन अमरीकी डॉलर (रू. 3,32,243 करोड़) था। एफडीआई इक्विटी

अन्तर्प्रवाह 41.042 बिलियन अमरीकी डॉलर था, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 28.61% अधिक था। वर्ष 2016-17 (अप्रैल - दिसम्बर) के दौरान भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अन्तर्प्रवाह 48 बिलियन डॉलर (रू. 3,21,940 **करोड़**) रहा है, जो वर्ष 2015-16 की इसी अवधि की तुलना में 22% अधिक है। वैश्विक स्तर पर विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अन्तर्प्रवाह में 13% की कमी आई है। जिसका प्रमुख कारण तेजी से बढ़ती राजनीतिक अस्थिरता तथा बदलते वातावरण में विश्वास की कमी है। भारत **में** 90% से अधिक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश ऑटोमैटिक मार्ग से आ रहा है। वर्ष 2016- 17 में सर्वाधिक 18% विदेशी प्रत्यक्ष निवेश सेवा क्षेत्रक में हुआ है। उसके बाद निर्माण विकास दूरसंचार, कम्प्यूटर हार्डवेयर तथा ऑटोमोबाइल्स का स्थान है।

अप्रैल 2000 से दिसम्बर 2016 की अवधि में कुल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अन्तर्प्रवाह 472.199 बिलियन डॉलर रहा है। इसी अवधि में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश ईक्विटी अन्तर्प्रवाह 183.897 बिलियन डॉलर रहा। अप्रैल 2000 से दिसम्बर 2016 की अवधि विश्व के शीर्ष पांच देशों से होने वाली विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अन्तर्प्रवाह निम्नलिखित प्रकार रहा (बिलियन डॉलर) -मॉरिशस 108.729 , 34% सिंगापुर 52.994, 18% यु के 24.374, 8% जापान 25.215, 8% यू. एस. ए. 19.884, 6% ।

अप्रैल 2000 - दिसम्बर 2015 की अवधि में सर्वाधिक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश महाराष्ट्र, दादरा नागर हवेली, दमन एवं दीव 100.165 बिलयन डॉलर (31%) क्षेत्र को प्राप्त हुआ है। दिल्ली-हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश के कुछ भागों को 660994 बिलयन डॉलर (21%), तमिलनाडु एवं पाण्डिचेरी को 22.647 बिलयन डॉलर (7%) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्राप्त हुआ।

UNCTED द्वारा किए गए World Investment Prospectus Survey, 2015 के अनुसार, भारत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को आकर्षित करने वाला महत्वपूर्ण देश **बन** गया है। पूरे विश्व **में** विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में **भारत का** हिस्सा जो 2000 **में** 0.3% था, वह 2015 में बढ़कर 3.6% हो गया।

यद्यपि भारत के कुल विदेशी निवेश में वृद्धि हुई है, परन्तु फिर भी अन्य देशों की तुलना में काफी कम है, इसके लिए उत्तरदायी कारण निम्नलिखित हैं (i) पूंजी खातें में रूपए का परिवर्तनीय न होना, (ii) अनेक क्षेत्रों में विदेशी निवेश की उच्चतम सीमा निर्धारित होना, (iii) भूमि अधिग्रहण, पर्यावरण तथा आधारभूत संरचना से जुड़ी समस्याएं। यद्यपि इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि विश्वव्यापी वित्तीय संकट के कारण विदेशी निवेश में कमी आयी है, किन्तु आने वाले समय में विदेशी निवेश बढ़ने की सम्भावना है।

भारत में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश

निवेश ऋणात्मक रहा, इसका अर्थ है कि इस वर्ष के दौरान भारतीय बाजारों में विदेशी पूंजी की निवल निकासी इस मद में हुई। समीक्षा के अनुसार वर्ष 2008 की वैश्विक मंदी के पश्चात् ऐसा पहली बार 2016 में हुआ। 2010 **से** 2016 के दौरान भारत में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के उपर्युक्त आंकड़े नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लि. (NSDL) के हवाले से आर्थिक समीक्षा में दर्शाए गए हैं।

समीक्षा में बताया गया है कि 2016 में एफपीआई की निकासी केवल भारतीय बाजारों से जुड़ी प्रक्रिया ही नहीं थी । विकसित अर्थव्यवस्थाओं में बेहतर प्रतिफल मिलने की प्रत्याशा में अधिकांश उभरती अर्थव्यवस्थाओं में बड़े पैमाने पर पोर्टफोलियो / संस्थागत निवेश की निकासी हुई। भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश मानकों का परिवर्तन - संघीय सरकार ने 20 जून, 2016 को अनेक क्षेत्रों में ऑटोमैटिक मार्ग से 100% विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को अनुमन्य कर दिया। अब भारत में केवल नकारात्मक सूची को छोड़कर अधिकांश क्षेत्रकों में स्वचालित मार्ग से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अनुमन्य हो गया है।

इस हालिया परिवर्तन में विश्व में भारत सर्वाधिक खुली अर्थव्यवस्था वाला देश **हो** गया है। 100% विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अब निम्नलिखित क्षेत्रकों में उपलब्ध हैं –

1. **भारत में विनिर्मित / उत्पादित खाद्य पदार्थ -** सरकारी अनुमोदन मार्ग से 100% खाद्य पदार्थों का व्यापार (ई - कॉमर्स सहित) |

2. **फार्मास्युटीकल्स** - ग्रीनफील्ड फार्मा में स्वचालित मार्ग से 100%; ब्रॉडनफील्ड फार्मा से 74% एफडीआई स्वचालित मार्ग से तथा इससे अधिक सरकार के अनुमोदन **से ।**

3. प्रसारण **करने** वाली सेवाएं - टेली-पोर्टस् (हब / टेलीपोर्टस् अपलिंकिंग की स्थापना; डायरेक्ट टु होम; केबिल नेटवर्क (मल्टी- सिस्टम ऑपरेटर्स MSOs) जो राष्ट्रीय या प्रान्तीय या जिला स्तर पर सेवाएं देते हैं एवं नेटवर्क के डिजिटलीकरण एवं सम्बोधनीयता के उच्चारण हेतु); हेड एण्ड स्काई ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज (HITS) ।

4. नागरिक उड्डयन - ग्रीनफील्ड एयरपोर्टस् स्वचालित मार्ग से 100% बॉडनफील्ड एयरपोर्टस् स्वचालित मार्ग से 100% FDI, एयर ट्रांसपोर्ट सेवा / घेरलू अधिसूचित यात्री एयरलाइन एवं क्षेत्रीय वायु परिवहन सेवाएं - 49%FDI स्वचालित मार्ग से तथा इससे अधिक (100%) सरकारी अनुमोदन **से** अनिवासी **भारतीय** 100% तक FDI स्वचालित मार्ग से निवेश कर सकते हैं; विदेशी एयरलाइन्स भारतीय एयर लाइन्सों में सरकारी अनुमति से 49% तक पूंजी लगा सकते हैं।

5. **पशुपालन** मत्स्य संवर्धन, मत्स्यापालन एवं मधुमक्खी पालन तथा पशुपालन बिना किसी शर्त के 100% FDI स्वचालित मार्ग से।

6. 10 जनवरी 2018 को सरकार ने सिंगल ब्रांड में सौ फीसदी विदेशी 1 निवेश को ऑटोमेटिक रूट से अनुमति देने का फैसला किया है। साथ ही खुदरा बाजार में संलग्न ऐसी कंपनियों के **लिए** 30 फीसदी भारत में खरीदी की शर्त भी हटा ली है। क्या यह फैसला देश में उत्पादन और रोजगार बढ़ाने में सहायक होगा ? क्या इससे मेक इन इंडिया कार्यक्रम पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा ?

निष्कर्ष एवं सुझाव - कपड़ा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) विगत दो साल में तीन गुना बढ़ा । वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय जल्द ही जारी करेगा एकीकृत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) नीति का नया संस्करण | देश में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) 37 प्रतिशत बढ़कर 10.4 अरब डॉलर हुआ। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में आई 72.72 करोड डॉलर का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) । चीन और अमेरिका को भारत ने पीछे किया। दूसरे साल भी भारत में सबसे ज्यादा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) आया। अप्रैल 2000 से सितम्बर 2016 तक भारत में आया 300 अरब डॉलर का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) ।

भारत में 2016-17 में मॉरीशस से आया सबसे अधिक (FDI) सिंगापुर को किया पीछे, जबकि 2015-16 में सिंगापुर पहले स्थान पर था। जापान को पीछे छोड़कर विदेश निवेशकों के लिए भारत बना 5वीं आकर्षक अर्थव्यवस्था। मौजूदा वित्त वर्ष की पहली छमाही में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) में 17% बढ़ोत्तरी हुई। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने भी भारत की तेज विकास दर का अनुमान लगाया है, जो भारत के विकास के लिए शुभ संकेत है।

अत: स्पष्ट है कि भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का दायरा निरन्तर बढ़ता जा रहा है, साथ ही इसके मानकों में भी उदार प्रवृत्ति को अपनाया जा रहा है क्योंकि देश के तीव्रतम आर्थिक विकास के लिए निवेश व तकनीकी की अत्यन्त आवश्यकता है जो हमें विदेशों से प्राप्त हो सकती है, इसीलिए वर्तमान में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश पर अधिकाधिक ध्यान केन्द्रित कर विदेशी नीतियों में परिवर्तन किया जा **रहा** है, परन्तु इसके साथ ही साथ यह भी ध्यान रखना आवश्यक होगा कि इसके सामने कहीं हमारा घरेलू उद्योग व्यापार बौना न रह जाए। यदि हम अपने उद्योग एवं व्यवसाय की बागडोर विदेशियों के हाथ में सौंप दें, तो निश्चित रूप से भविष्य में समस्याओं का सामना करना पडेग़ा। अत: अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के खतरे भविष्य में हमारे सामने आएंगे और यह देश के हित में भी नहीं होगा, क्योंकि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से पराधीनता का खतरा, स्वतन्त्र आर्थिक नीति अपनाने में कठिनाई, विदेशों पर निर्भरता, भुगतान में कठिनाई, आन्तरिक वित्तीय **साधनों** का अपर्याप्त विकास, राष्ट्रीय एवं बड़े उत्पादकों के लिए हानिकारक, देश का असन्तुलित एवं अव्यवस्थित विकास, वित्तीय अनिश्चितताएँ, आर्थिक शक्ति का केन्द्रीयकरण तथा लाभों का निर्यात होने लगता है । विदेशी प्रत्यक्ष निवेश योजनाबद्ध तरीके से किया जाना चाहिए ताकि प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों, निर्यातोन्मुखी उद्योगों तथा पर्यटन क्षेत्रों में यह पूँजी लगाइ जा सके। युवाओं के

रोजगार, उत्पादन**, जनता** की क्रयशक्ति पर सकारात्मक प्रभाव ही भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाकर विकसित देश की श्रेणी में खड़ा कर सकता है, जबकि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की नीतियों को देशहित में क्रियान्वित किया जाए व इसके सभी पहलूओं पर गहराई से विचार करते हुए उचित मॉडल अपनाया जाए। भारत की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, भौगोलिक तथा पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुसार ही विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि आर्थिक विकास के साथ- साथ सभ्यता, संस्कृति, पर्यावरणीय तथा मानवीय मूल्यों एवं हितों का संरक्षण भी अत्यन्त आवश्यक है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. रूद्र दत्ता के. पी. एम. सुन्दरम, भारतीय अर्थव्यवस्था, एस. चन्द्र एण्ड कंपनी लिमिटेड नई दिल्ली 2011
2. अग्रवाल एवं बला, अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, आगरा
3. डॉ. शिवनारायण गुप्त, अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, रामप्रसाद एण्ड सन्स आगरा 2009
4. डॉ. अनुपम अग्रवाल एवं एस. के. शर्मा अर्थशास्त्र व्यष्टि एवं समष्टि एस. बी. पी. डी. पब्लिकेशन्स
5. आर्थिक समीक्षा 2016-17
6. प्रतियोगिता दर्पण - भारतीय अर्थव्यवस्था वार्षिकी 2012-13
7. पत्रिका सागर 16.01.2018
8. पत्रिका सागर 22.01.2018
9. पत्रिका सागर 24.01.2018 कमोडिटी एक्सचेन्ज